

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 26 नवम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/58-86/44358.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० वीनैक्स, प्लॉट नं. 24, घाखुहेड़ा, गुड़गांव के महासचिव दी डिस्ट्रिक्ट, महेन्द्रगढ़ टैंक्सटाईल वर्करज यूनियन (रज.), रिवाड़ी, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्रमिकों के सलग्न मांग-पत्र में दी गई वोनस की मांग का कोई औचित्य है? यदि हां, तो किस विवरण में ?

कुलबन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार विभाग ।

दिनांक 26 नवम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/104-84/44413.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० नार्दन इन्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, 20/3, मयूरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री श्याम सुन्दर, पुत्र श्री रिसाल सिंह मार्फत श्री सुनेहरी लाल, लेबर लीडर अहीरवाड़ा बल्लबगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री श्याम सुन्दर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 1 दिसम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/165-86/44870.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डियन हाइवेयर इण्डस्ट्रीज लि०, हाईवेयर चीक एन. आई. टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री एस. पी. मिश्रा, मार्फत विधि सचिव, इण्डियन हाईवेयर इण्डस्ट्रीज वर्कर यूनियन, 1-ए/119 एन. आई. टी. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री एस. पी. मिश्रा की सेवा समाप्त की गई है? या उसने स्वयं गैर-हाजिर होकर नीकरी से पूर्णग्रहणाधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?